

आईएमसीजी की बैठक

प्रलिस के लिये:

नेबरहुड फरस्ट नीति, सार्क, क्वाड

मेन्स के लिये:

नेबरहुड फरस्ट नीति और चुनौतियाँ, भारत की 'नेबरहुड फरस्ट नीति' का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के वदेशि सचवि द्वारा सचवि स्तर पर अंतर-मंत्रसित्रीय समन्वय समूह (Inter-Ministerial Coordination Group- IMCG) की पहली बैठक बुलाई गई ।

- IMCG को भारत की 'नेबरहुड फरस्ट नीति' के दृष्टिकोण को मुखयधारा में लाने की दशिा में एक उच्च-स्तरीय तंत्र के रूप में स्थापति कयिा गया है, जसिका बल भारत के पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंघ वकिसति करने पर है ।
- IMCG को वदेशि मंत्रालय में संयुक्त सचवियों द्वारा बुलाई गई अंतर-मंत्रालयी संयुक्त कार्य बल (Joint Task Forces- JTF) द्वारा समर्थति कयिा जाता है ।

प्रमुख बिदि

बैठक की मुखय वशिषताएँ:

- बैठक के बारे में:
 - IMCG ने बेहतर कनेक्टविटी, मज़बूत इंटरलकिंज और पड़ोसी देशों के नागरिकों के मध्य मज़बूत जुड़ाव को बढ़ावा देने हेतु एक संपूरण सरकारी दृष्टिकोण के साथ व्यापक दशिा प्रदान की ।
 - बैठक का फोकस सीमा अवसंरचना का नरिमाण करना था जो नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ अधकि व्यापार की सुवधिा प्रदान करने, आवशयक वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में भूटान और मालदीव जैसे देशों की वशिष ज़रूरतों को पूरा करने, [बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क खोलने](#), अफगानसिस्तान और म्याँमार को मानवीय सहायता प्रदान करने तथा [श्रीलंका के साथ मतस्य पालन](#) के मुद्दे पर केंद्रति था ।
- महत्त्व:
 - IMCG देशों की सरकारों के मध्य संस्थागत समन्वय में और अधकि सुधार करेगा तथा अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंघों के लयि इस पूरे सरकारी दृष्टिकोण को व्यापक दशिा प्रदान करेगा ।

नेबरहुड फरस्ट नीति वज़िन का उद्देश्य:

- कनेक्टविटी:
 - भारत द्वारा दक्षिण एशियाई कषेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के सदस्यों के साथ समझौता जज़ापन पर हस्ताक्षर कयिा गए हैं । ये समझौते सीमाओं के पार संसाधनों, ऊर्जा, माल, श्रम और सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चिति करते हैं ।
- पड़ोसी देशों के साथ संबंघों में सुधार:
 - भारत की प्राथमकिता तत्काल पड़ोसी देशों के साथ संबंघों में सुधार करना है क्योंकि विकास के एजेंडे को साकार करने के लयि दक्षिण एशिया में शांति आवशयक है ।
- संवाद:
 - यह पड़ोसी देशों के साथ जुड़कर और बातचीत के माध्यम से राजनीतिक संबंघों का नरिमाण करके मज़बूत कषेत्रीय कूटनीति पर ध्यान केंद्रति करता है ।
- द्वपिकषीय वविादों का समाधान:

- नीति आपसी समझौते के माध्यम से द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने पर केंद्रित है।
- **आर्थिक सहयोग:**
 - यह पड़ोसियों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत इस क्षेत्र में विकास के एक माध्यम के रूप में सार्क में शामिल हुआ है और इसमें नविश कथित है।
 - 'ऊर्जा विकास के लिये ऐसा ही एक उदाहरण बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (Bangladesh-Bhutan-India-Nepal- BBIN) समूह अर्थात् मोटर वाहन, जलशक्ति प्रबंधन और इंटर-ग्रिडि कनेक्टिविटी है।
- **आपदा प्रबंधन:**
 - यह नीति आपदा प्रतिक्रिया, संसाधन प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान और संचार पर सहयोग करने तथा सभी दक्षिण एशियाई नागरिकों हेतु आपदा प्रबंधन में क्षमताओं एवं विशेषज्ञता पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- **सैन्य और रक्षा सहयोग:**
 - भारत वभिन्न रक्षा अभ्यासों के आयोजन में भाग लेकर सैन्य सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चिता करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

नेबरहुड फ्रस्ट नीति से संबंधित मुद्दे:

- **चीन का बढ़ता दबाव:**
 - भारत की 'नेबरहुड फ्रस्ट नीति' एक सार्थक दिशा प्रदान करने में विफल रही है और बढ़ते चीनी दबाव ने देश को इस क्षेत्र में सहयोगी पक्षों का समर्थन प्राप्त करने से रोक दिया है।
 - समुद्री मोर्चे पर चीन हृदि-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।
 - **बेल्ट एंड रोड इनशिएटिवि (BRI)** चीन को भारत के पड़ोस में विस्तार करने का अवसर भी प्रदान करती है, उदाहरण के लिये **चीन-पाकस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC)** के कारण चीन की उपस्थिति भारतीय सीमा के करीब देखी गई है, चाहे वह **पाकस्तान अधिकृत कश्मीर** में हो या **सर क्रीक क्षेत्र**।
 - वर्ष 2013 में प्रस्तावित BRI चीन का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है।
- **घरेलू मामलों में हस्तक्षेप:**
 - भारत अपने पड़ोसी देशों विशेषकर नेपाल के घरेलू मामलों में उसकी संप्रभुता में हस्तक्षेप कर रहा है।
 - भारत, नेपाल के अंदर और बाहर मुक्त पारगमन व मुक्त व्यापार में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है तथा अपने लोगों और सरकार पर दबाव बनाता रहता है।
- **सैन्य उपायों पर ध्यान केंद्रित करना:**
 - भारत सामाजिक तत्त्वों के बजाय सैन्य उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने में मदद की है, जिससे भारत वरिधी भावना में वृद्धि हो रही है।
- **भारत की घरेलू राजनीति का प्रभाव:**
 - भारत की घरेलू नीतियाँ **मुसलमि-बहुल देश बांग्लादेश** में समस्याएँ पैदा कर रही हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत की **नेबरहुड फ्रस्ट नीति को बांग्लादेश जैसे मैत्रीपूर्ण क्षेत्रों में भी गंभीर चुनौतियों** का सामना करना पड़ रहा है।
 - कई बांग्लादेशी वर्तमान में भारत के राजनीतिक नेतृत्व को **इसलामोफोबिक या इसलाम वरिधी** मानते हैं।
- **पश्चिम की ओर भारत के झुकाव का प्रभाव:**
 - भारत विशेष रूप से **कवाड** और अन्य **बहुपक्षीय तथा लघु-पारश्व पहलों** के माध्यम से पश्चिम के साथ करीबी संबंध स्थापित कर रहा है।
 - लेकिन पश्चिम के साथ श्रीलंका के संबंध अच्छी दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि देश की वर्तमान सरकार को **मानवाधिकारों के मुद्दों** और स्वतंत्रता पर पश्चिमी देशों से बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
 - नतीजतन, श्रीलंका ने चीन के अपने संबंधों को मज़बूत करना शुरू कर दिया है, जिससे यह संभावना बढ़ गई है कि भारत-श्रीलंका के संबंध किसी समय खराब हो सकते हैं।

आगे की राह

- भारत की **नेबरहुड फ्रस्ट नीति** गुजराल सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिये।
 - इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत के कद और ताकत को उसके पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों की गुणवत्ता से अलग नहीं किया जा सकता है तथा उनका क्षेत्रीय विकास भी हो सकता है।
- भारत की क्षेत्रीय आर्थिक और विदेश नीति को एकीकृत करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- इसलिये भारत को छोटे आर्थिक हितों के लिये पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों से समझौता करने का वरिध करना चाहिये।
- क्षेत्रीय संपर्क को अधिक मज़बूती के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिये, जबकि सुरक्षा चिंताओं को लागत प्रभावी, कुशल और विश्वसनीय तकनीकी उपायों के माध्यम से संबोधित किया जाता रहा है जो दुनिया के अन्य हस्सिों में उपयोग में हैं।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में आने वाले 'बेल्ट एंड रोड इनशिएटिवि' किसके मामलों के संदर्भ में आता है? (2016)

- अफ्रीकी संघ
- ब्राज़ील
- यूरोपीय संघ

(d) चीन

उत्तर: (d)

स्रोत: द हद्दू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/meeting-of-imcg-on-neighbouring-countries>

